



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 ज्येष्ठ 1944 (श0)
(सं० पटना 357) पटना, सोमवार, 13 जून 2022

सं० 08/आरोप-01-118/2015 सा0प्र0-8349
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
27 मई 2022

श्री सुधीर कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-668/2011 तत्कालीन प्रभारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा के विरुद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-104 दिनांक 08.01.2016 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र में श्री कुमार के विरुद्ध निगम मुख्यालय द्वारा मिलो से एकरारनामा करने के संबंध में दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं करने, परिवहन हेतु अधिक दूरी दर्शाने, सी०एम०आर० प्राप्त करने के पूर्व अग्रिम राशि का भुगतान करने, सी०एम०आर० एवं अन्य खर्च में प्रति क्वी० अधिक व्यय करने एवं अधिप्राप्ति धान के विरुद्ध अग्रिम सी०एम०आर० प्राप्त नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक 1305 दिनांक 27.01.2016 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार ने अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक 68 दिनांक 08.02.2016) समर्पित किया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 2961 दिनांक 26.02.2016 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 210 दिनांक 15.01.2020 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ।

3. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6080 दिनांक 24.06.2020 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

4. मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक 988 दिनांक 28.12.2021 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। मुख्य जांच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया है, किन्तु श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन उप प्रमुख, दावा/निगरानी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है। आरोप पत्र के साथ संलग्न जांच प्रतिवेदन में आरोप संख्या-04 के संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि :-

“जिला प्रबंधक, मधेपुरा के मांग पत्र एवं पारित विपत्र में स्पष्ट होता है कि धान एवं सी0एम0आर0 के परिवहन, हथालन तथा मिलिंग चार्ज के रूप में कुल 2,05,86,525/— रु0 मेसर्स न्यू प्रिन्स राईस मिल को भुगतान करनी पड़ेगी। पूर्व में किये गये भुगतान एवं बकाया राशि को देखा जाय तो सी0एम0आर0 के प्रति क्विंटल पर 420/— रु0 से अधिक खर्च वहन करना पड़ेगा।”

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-18(2) के प्रावधानों के तहत संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से उक्त बिन्दुओं पर असहमति व्यक्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-18(3) के प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक 4790 दिनांक 29.03.2022 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त क्रम में श्री कुमार के पत्रांक 25 दिनांक 11.04.2022 द्वारा अपना लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं जांच प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दु पर श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक पदाधिकार के स्तर पर की गयी एवं पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विपत्र निगम मुख्यालय के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा बनाया गया था। इसलिए अगर विपत्र में गलती हुई भी थी तो वह चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की गयी थी, किन्तु आरोपित पदाधिकारी को इसकी जांच करनी चाहिए थी।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सुधीर कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-668/2011 तत्कालीन प्रभारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा का लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है तथा श्री कुमार द्वारा विपत्र की जांच नहीं करने/लापरवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 में उल्लिखित निम्नांकित दंड उन्हें अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:-

(1) निन्दन (वर्ष-2014-15)

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 357-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>